प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

25.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि केन्द्रीय उपक्रमों एनएचपीसी व एसजेवीएन को वापिस लिया जाएगा और इन परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त जमीन भी उनसे वापस ली जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी और एसजेवीएन को बिजली परियोजनाएं दी गई हैं और उनके लिए हिमाचल सरकार की शर्तों को नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएचपीसी का बैरास्यूल प्रोजेक्ट व चमेरा–एक प्रोजेक्ट 40 साल पुराना हो चुका है और कायदे से इसे सरकार को लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि 12 फीसदी मुफ्त रॉयल्टी में हमेशा के लिए उनके पास परियोजनाएं रहेंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन सभी मसलों पर सरकार कानूनी राय लेते हुए आगे बढ़ रही है। विधायक हंसराज के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय उपक्रमों के साथ लंबी लड़ाई चलने वाली है और इस लड़ाई की शुरूआत उनकी सरकार ने कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि कोई भी परियोजना 40 साल के लिए ही दी जाएगी और 12, 18 व 30 फीसदी बिजली रॉयल्टी की शर्त भी रहेगी। विधायक जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 16 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं, जहां हिंदी भाषा के शिक्षकों का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित इन स्कूलों में सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए कोई नियुक्त शिक्षक नहीं है। विधायक लोकेंद्र कुमार, रणधीर शर्मा और बिक्रम सिंह द्वारा पूछे गए संयुक्त प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही गोबर खरीद योजना के तहत बीते दो वर्षों में एक सौ 5 पशुपालकों से कुल 4 सौ 21 क्विंटल कम्पोस्ट खाद की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने प्रति किलो तीन रुपये की दर से भुगतान किया, जिससे कुल एक लाख 26 हज़ार 3 सौ रुपये की राशि किसानों को प्राप्त हुई। चंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों से कम्पोस्ट खाद की खरीद की गई।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में गलत तथ्य रखने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नालागढ़ में खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सदन में गलत तथ्य पेश किए गए जबकि खनन के लिए ज़मीन कांग्रेस सरकारों के समय में दी गई।

सिकंदर कुमार

हिमाचल प्रदेश में जलाशयों का जल स्तर काफी गिर गया है और इसका असर जल विद्युत उत्पादन व फसलों की सिंचाई पर पड़ सकता है। राज्यसभा में सांसद डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि राज्य के जलाशयों में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा 13 मार्च 2025 को जारी बुलेटिन के अनुसार हिमाचल के तीन प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज कम हो गई है राज भूषण चौधरी ने बताया कि इस वर्ष जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति सामान्य से 33 फीसदी कम दर्ज की गई है, जिससे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कम वर्षा और बर्फबारी के कारण केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी की है और राज्य सरकार से इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।